(2) खादी की बिक्री पर छूट देने का प्रावधान ।

(3) खादी की खरीद को प्राथमिकता देना ।

(4) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत डिजाईनों का शुरू करना ।

(5) खिादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के जरिए वपणन में सहायता देना ।

मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

789. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राजू भाई ए परमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश से केन्द्रीय सरकार को उद्योग लगाने के कितने प्रस्ताव प्रति वर्ष प्राप्त हुए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए और कितने प्रस्तादों को अस्वीकार कर दिया गया;

(ग) प्रस्तावों को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) मंजूरी के लिए लम्बित प्रस्तावों का शीघ्र निपटारा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहो) : (क) और (ख) निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया है कि पिछले तीन वर्षों में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, कितने अनुमोदित हुए (आशय पत्र जारी हुए) और कितने अस्वीकार किये गये :—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	(30.6.92 को) दिये गये आशय पत्रों की संख्या	अस्वीकृत
1989	252	51	123
1990	139	40	69
1991	144	16	26

(ग) अस्वीकृत होने के कारण प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न होते हैं। इनमें आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य/तकनीकी रूप से स्वस्थ न होने/अच्छी तरह तैयार न किये गये प्रस्ताव, चालू नीतिगत दिशानिर्देशों के अधीन न आने वाली निर्माण की मद स्थापना-स्थल दृष्टिकोण, उद्योग के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने वाला प्रस्ताव, निर्माण की प्रस्तावित रूपरेखा पर क्षमता के आगे लाइसेंसीकरण/सृजन की कोई गुंजाइश नहीं, कच्चे माल की दिक्कत आदि शामिल हैं।

(घ) अधिकांश लम्बित मामले बीयर, पोटेबल एल्कोहल तथा चीनी से संबंधित हैं। इन मामलों का निपटान अलग अलग प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा इस संबंध में अपनाई गई नीति पर निर्भर करता है।

देश में लघु उद्योग क्षेत्र का विकास किया जाना

790. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राजू भाई ए० परमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना लागू करने पर विचार कर रही है:

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या-क्या हैं जहां इस योजना को लागू किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) सरकार देश में लघु क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए अनेक योजना स्कीमों को कार्यान्वित कर रही हैं। कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजना स्कीमें औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्रों, परीक्षण केन्द्रों, प्रक्रिया और उत्पाद विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों,

उद्यमियता विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रबन्ध प्रशिक्षण, अनुषंगी विकास, विपणन सहायता और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से संबंधित हैं। उपर्युक्त योजना स्कीमों के अधीन सेवाएं और सुविधाएं सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में लघु उद्योगों को उपलब्ध हैं। इसके अलावा, ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एकीकृत बुनियादी विकास योजना के बारे में केन्द्र और राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों से संबंधित प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Setting up of Agro based industry in Punjab

791. SHRI JAGIR SINGH DARD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state whether Government propose to establish/set up Agro based industry in Punjab in order to check unemployment, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN): Punjab being relatively rich in agriculture, need for promotion of agro-based industries in the State is well recognized. The State Government, has therefore, laid major stress on the promotion of these industries. Various organisations such as the Punjab State Agro Industries Corporation, MARKFED, SUGARFED, SPINFED, PUNTEX, the Punjab State Industrial Development Corporation and the Agro Industries Cell in the Directorate of Industries, Punjab are engaged in the promotion of agro-based industries in the State.

Purchase of raw materials by Cement Plants of Cement Corporation of India

792. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all purchases of raw material by cement plants of the Cement Corporation of India are being centralised;

(b) if so, what are the reasons thereof;

(c) whether there are any guidelines issued to public sector units not to increase centralisation; and

(d) what steps are being taken to restore autonomy and freedom to individual cement plants?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) Not applicable.

(c) No, Sir;

(d) Cement plants of CCI have full autonomy and freedom for their day-to-day operations.

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

793. **श्री राम नरेश यादव**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार इस सूची में कुछ नए जिलों को शामिल किए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इन जिलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "ना" है तो उसके क्या कारण हैं; और